प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर महाकुंभ के आर्थिक प्रभाव का होगा अध्ययन

लखनऊ (एसएनबी)। प्रयागराज में सामाजिक समरसता के महापर्व महाकुंभ मेला के आयोजन से धार्मिक व अध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का भी सृजन हुआ है। महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन में 66 करोड़ से अधिक लोगों का आगमन हुआ। इससे प्रदेश के संगठित व असंगठित क्षेत्रों में वृद्धि हुई तथा रोजगार में भी बढ़ोत्तरी हुई है। अब प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर महाकुंभ के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए 11 शहरों से उनके तीन वित्तीय वर्ष की वार्षिक तथा दिसंबर, जनवरी व फरवरी के निकायवार आंकड़ों की रिपोर्ट मांगी गई है। महाकुंभ के आर्थिक प्रभाव के आकलन तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था के जल सम्पूर्ति एवं उपयोगी सेवाओं की जीडीपी के अनुमान तैयार करने के लिए 11 जनपदों का अध्ययन किया जाना है।

यूपी सरकार के इस बड़े आयोजन से कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 के आर्थिक पक्षों पर वैज्ञानिक तरीके से सम्यक प्रभावों के आकलन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि भारत सरकार के साथ महाकुम्भ के आर्थिक व सामाजिक प्रभावों के परिणामों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, ताकि यह आंकड़े केन्द्र सरकार के सैम्पल सर्वे में शामिल हो सकें। निदेशक अर्थ एवं संख्या के पत्र पर आर्थिक अध्ययन के लिए निदेशक नगर निकाय निदेशालय अनुज झा ने निकायों को तीन वार्षिक व तीन महीनों की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक समागम महाकुम्भ में अब तक देश-दुनिया के 66 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है।

इन 66 करोड़ से अधिक लोगों के आगमन से प्रदेश के संगठित व असंगठित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है तथा रोजगार में भी बढ़ोत्तरी हुई है। महाकुम्भ के आयोजन से प्रदेश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे प्रदेश की जीडीपी में लगभग साढ़े 3 से 4 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि होने वाली है। महाकुम्भ से हजारों करोड़ रुपये की अवस्थापना सुविधाएं विकसित की गईं। व्यापार, हॉस्पिटैलिटी, परिवहन, एमएसएमई, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में वृद्धि बड़ी उपलब्धि है। जीडीपी के अनुमान को तैयार करने के लिए 11 जनपदों प्रयागराज, महाकुंभ नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, मथुरा व आगरा की वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 की वार्षिक आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा गया है।